IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO Regd. Office
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 24 | अंक 14 | सांचौर, बुधवार, 15 जुलाई 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | UDYAM-RJ-19-0033346 | कुल पृष्ठ - 4

सहकारी योजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें: शासन सचिव

जयपुर, । सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में शासन सचिव व रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने अधिकारियों को निर्धारित समय में योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान कार्य में कोताही बरतने पर सीकर सीसीबी की अधिशाषी अधिकारी ज्योति सांई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वित्तीय पारदर्शिता के लिए सहकारी संस्थाओं का रैंडम टेस्ट ऑडिट कराया जाएगा और नियमों का पालन न करने वाली ऑडिट फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा, प्रशासनिक कार्यों के आधार पर खण्ड स्तर पर अजमेर और जिला स्तर पर खैरथल-तिजारा पहले स्थान पर रहे। बैठक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण गोदाम निर्माण और 20 जुलाई से पहले कस्टम हायरिंग सेंटर्स के काम को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए।

बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण

बाड़मेर: राज्य सरकार के 'हरियालो राजस्थान – एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक परिसर में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक अधिकारियों और कार्मिकों ने न केवल पौधे लगाए, बल्कि उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक जगदीश जागरीवाल ने पर्यावरण संतुलन को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए इसे सामूहिक जिम्मेदारी कहा। वहीं शाखा प्रबंधक मोतीलाल ने इस अभियान को माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और आने वाली पीढ़ियों को हरित वातावरण देने का एक सुंदर माध्यम बताया। इस अवसर पर गौरव पारीक, तगाराम, पदमाराम और रमेश सहित अन्य कार्मिकों ने भी राजस्थान को हरा-भरा बनाने का संकल्प लिया।

सहकार से संवरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था:

पैक्स कम्प्यूटरीकरण में देश में प्रथम पायदान पर राजस्थान, 10 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन लेनदेन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को नई उड़ान मिली है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु मिली है, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से सहकारी आंदोलन राजस्थान के हर गांव-ढाणी तक पहुंच गया है। प्रदेश में 42 हजार से अधिक सहकारी समितियों से 1 करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं। सहकार सदस्यता अभियान के जरिए 8 लाख 90 हजार नए सदस्य जुड़ने से 'सहकार परिवार' और मजबूत हुआ है।

भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन

मुख्यमंत्री ने बताया कि तकनीक के मोर्चे पर राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में 5 हजार 646 पैक्स को ई-पैक्स में बदला गया है। इनके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन हुए हैं, जो पूरे देश के कुल ट्रांजेक्शन का एक-तिहाई हिस्सा है। यह आंकड़ा देश में सर्वाधिक है। वहीं, 5 हजार 279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन और भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता दिलाने में भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0 और जियो टैग मोबाइल एप का भी शुभारंभ किया गया। समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और सहकार बंधु उपस्थित रहे।

जयपुर को मिली 'सहकार वन' की सौगात

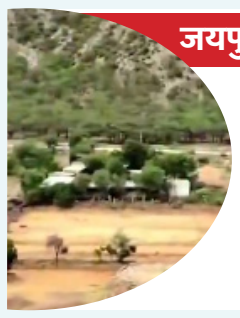

समारोह के दौरान राजस्थान के लिए कई सौगातें मिलीं। जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ जमीन पर 'सहकार वन' विकसित करने के लिए ई-भूमि पूजन किया गया, जिसमें मियावाकी और सामान्य प्रणाली से खेजड़ी, रोहिड़ा व नीम जैसे स्वदेशी वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में 50 गोदामों का लोकार्पण, 10 का शिलान्यास और 100 गोदामों का हस्तांतरण हुआ।

डेयरी से बदल रही तस्वीर

प्रदेश के डेयरी मॉडल की सराहना करते हुए सीएम ने कहा कि पशुपालकों के लिए यह आर्थिक संबल का बड़ा आधार बन गया है। 9 लाख 40 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हैं, जिनमें 4 लाख 20 हजार से अधिक महिलाएं हैं। डेयरी संघ अब मुनाफे में हैं और 10 हजार करोड़ का रिकॉर्ड टर्नओवर हासिल किया है। प्रदेश में दूध संकलन 38 लाख लीटर से बढ़कर 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है।

किसानों की आय बढ़ाने में सहकारिता बड़ा माध्यम

केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सहकारिता की मजबूती से ही ग्रामीण भारत सशक्त होगा। दुग्ध उत्पादन में भारत का शीर्ष स्थान और उसमें सहकारी समितियों का योगदान इस बात का प्रमाण है कि किसानों की आय बढ़ाने में सहकारिता सबसे बड़ा माध्यम है।

सहकारिता में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 21 केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिली नई कमान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान सहकारिता विभाग ने प्रदेश के सहकारी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक साहसिक और सकारात्मक कदम उठाया है।विभाग ने देर रात एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर प्रदेश की सभी 21 केंद्रीय सहकारी बैंकों में पहली बार पूर्णकालिक प्रबंध निदेशकों की तैनाती की है। यह निर्णय पिछले पांच वर्षों में सहकारिता विभाग द्वारा लिए गए सबसे बड़े और निर्णायक प्रशासनिक बदलावों में से एक माना जा रहा है सहकारिता विभाग के इस निर्णय के तहत राज्य सहकारिता सेवा के अतिरिक्त रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों को इन बैंकों की कमान सौंपी गई है। यह नियुक्ति न केवल बैंकों के संचालन को गति देगी, बल्कि उन्हें आरबीआई लाइसेंस शुद्धा वाणिज्यिक संस्थानों की तर्ज पर व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी भी बनाएगी प्रशासनिक कसावट से किसानों और आम सदस्यों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

सहकारिता मंत्री के विजन से मिली नई दिशा

जानकारों का कहना है कि यह फेरबदल प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के स्पष्ट विजन और उनके दिशा-निर्देशों का परिणाम है। विभाग ने लंबे समय से चली आ रही 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंड की मांग को पूरा करते हुए यह कदम उठाया है। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य सहकारी बैंकों के प्रबंधन में जवाबदेही तय करना और किसान हितैषी सेवाओं में पारदर्शिता लाना है।

सहकार जगत में खुशी, नेतृत्व के प्रति उम्मीदें

इस सकारात्मक पहल का सहकारी आंदोलन से जुड़े प्रबुद्धजनों ने स्वागत किया है। सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि, "सीसीबी में पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक लगाना एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे जमीनी स्तर पर सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलेगी और बैंकों के कामकाज में नई ऊर्जा का संचार होगा।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

दी सिरोही सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
द्वारा आयोजित सहकार सप्ताह (वर्ष 2026-27) के अवसर पर,
श्री रमेश कुमार (व्यवस्थापक, पैक्स-उड़)
को सहकारिता के क्षेत्र में उनके अत्यंत उल्लेखनीय एवं सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किए जाने पर
हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं
:::: शुभेच्छु ::::
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक बोर्ड सदस्य गण
पैक्स स्टाफ एवं समस्त ग्रामवासी
उड़ बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि, उड़. तहसील व जिला: सिरोही (राज.)

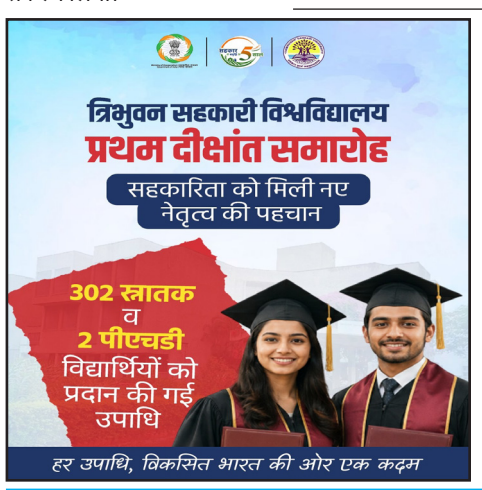

सहकारी केंद्रों पर अब मिलेंगे किसानों के जैविक उत्पाद, निर्देश जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार अब किसानों के जैविक (ऑर्गेनिक) उत्पादों को बेचने के लिए सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों और क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के बिक्री केंद्रों पर मंच (प्लेटफॉर्म) उपलब्ध कराएगी। यह घोषणा हाल ही में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा की गई थी, जिसके तुरंत बाद रजिस्ट्रार कार्यालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त रजिस्ट्रार केदारमल मीणा ने सभी खंडों के अधिकारियों को सक्रिय सहकारी इकाइयों के माध्यम से किसानों से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। कॉनफैड के प्रबंध संचालक इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेंगे। इस पहल से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को सही मूल्य मिलेगा और आमजन को शुद्ध उत्पाद मिल सकेंगे।

सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस पर कानेटी में 500 एमटी गोदाम का शिलान्यास

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

अलवर। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर अलवर की कानेटी बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर क्षेत्र के किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले नवीन भंडारण गोदाम का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता डॉ. बन्ना राम मीना थे, जबकि अध्यक्षता समिति अध्यक्ष महावीर सिंह राजपूत ने की। इस मौके पर उप रजिस्ट्रार गुलाब चंद मीना और बैंक अधिकारी ऋचा सैनी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समिति के व्यवस्थापक देवेंद्र कुमार सैदावत ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि यह गोदाम किसानों को भंडारण की समस्या से निजात दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा।

सहकार समृद्धि फाउंडेशन की पहली बैठक 16 को

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकार समृद्धि फाउंडेशन के गठन की वैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब संस्था ने अपने सेवा कार्यों की दिशा तय करने के लिए कमर कस ली है। फाउंडेशन की प्रथम संस्थापक बैठक का आयोजन 16 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक सिंधी कैंप स्थित रूबी होटल में किया जाएगा संस्थापक सदस्य देवेंद्र कुमार सैदावत ने बताया कि फाउंडेशन का ध्येय 'सहकार से समृद्धि की ओर' है। यह संस्था केवल सहकारिता तक सीमित न रहकर शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन जैसे जनकल्याणकारी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएगी बैठक में फाउंडेशन के सभी 18 संस्थापक सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में संस्था की आगामी कार्ययोजना तैयार करने के साथ ही भविष्य के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने हेतु ठोस रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। फाउंडेशन के पदाधिकारियों का मानना है कि यह बैठक समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक सशक्त माध्यम साबित होगी।

जोधपुर सहकारिता: अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर प्रशांत कल्ला की ताजपोशी, संभाग के 'अनुभव' पर भरोसा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर। संभाग में सहकारिता विभाग के प्रशासनिक ढांचे में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। लंबे समय से चल रही कयासबाजियों पर विराम लगाते हुए सरकार ने विभाग के महत्वपूर्ण पद 'अतिरिक्त रजिस्ट्रार' (जोधपुर खंड) की कमान सहकारिता सेवा के संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी प्रशांत कल्ला को सौंपी है। कल्ला की नियुक्ति को संभाग की सहकारी गतिविधियों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है प्रशांत कल्ला की नियुक्ति के पीछे उनका वर्षों का अनुभव मुख्य आधार रहा है। जोधपुर संभाग की सहकारी व्यवस्थाओं में कल्ला एक जाना-पहचाना नाम हैं। अपने लंबे सेवाकाल में वे जालौर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक जैसे अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। इसके साथ ही, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी के रूप में विभागीय बारीकियों को समझने का अनुभव भी उन्हें अन्य दावेदारों से अलग खड़ा करता है। पिछले एक दशक से संभाग में सक्रिय रहने के कारण उन्हें यहां के सहकारी ढांचे और कार्यप्रणाली की गहरी समझ है

लोकल' चेहरों का रहा है दबदबा

जोधपुर खंड के अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालय का इतिहास रहा है कि यहां ज्यादातर उन्हीं अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है, जो या तो स्थानीय हैं या जिनका कार्यक्षेत्र लंबे समय से यही रहा है। 4 मार्च 2014 को जब 'संयुक्त रजिस्ट्रार' के पद को अपग्रेड कर 'अतिरिक्त रजिस्ट्रार' का पद सृजित किया गया, तब से अब तक राजेंद्र चौधरी, केशराराम चौधरी, धनसिंह देवल, शुद्धोधन उज्जवल और देवेंद्र अमरावत जैसे स्थानीय चेहरों का ही दबदबा रहा है।

विवादों और फैसलों से पुराना नाता

यह पद हमेशा से सुर्खियों में रहा है। अतीत पर नजर डालें तो सहकारिता सेवा के अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी भोमाराम का कार्यकाल सबसे अधिक चर्चाओं में रहा। उनके दो साल के कार्यकाल में जहां नीतिगत फैसलों ने विभाग को नई पहचान दी, वहीं कई निर्णय विवादों के घेरे में भी रहे। वर्ष 2022 में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका हो या सहकारी संस्थाओं के विज्ञापनों पर रोक लगाने का चर्चित निर्णय, विभागीय हलकों में आज भी इसकी चर्चा होती है।

2014 से अब तक का सफर

जोधपुर सहकारिता विभाग के इस कार्यालय ने संभाग की सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभाई है। 2014 से पूर्व जब यह पद 'संयुक्त रजिस्ट्रार' स्तर का था, तब उमराव सिंह चारण, रामचंद्र सिंह जोधा अविनाश रिणवा प्रदीप जैन जैसे अधिकारियों ने विभाग को संभाला था। वहीं, पद अपग्रेड होने के बाद वाई.एस. यादव, सोहनलाल लखानी और अनिल मेहता जैसे अधिकारियों ने भी समय-समय पर अपनी सेवाएं दीं अब प्रशांत कल्ला के सामने न केवल पुरानी व्यवस्थाओं को गति देने की चुनौती होगी, बल्कि संभाग में सहकारिता के प्रति आमजन का विश्वास और संस्थागत सुधारों को नई दिशा देने की जिम्मेदारी भी होगी।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

दी जालोर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
द्वारा आयोजित सहकार सप्ताह (वर्ष 2026-27) के अवसर पर,
श्री मधुसुदन शर्मा (व्यवस्थापक, पैक्स-उम्मेदाबाद)
को सहकारिता के क्षेत्र में उनके अत्यंत उल्लेखनीय एवं सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किए जाने पर
हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं
:::: शुभेच्छु ::::
श्री नगेन्द्र कुमार गुरासा अध्यक्ष एवं समस्त संचालक बोर्ड सदस्य गण पैक्स स्टाफ एवं समस्त ग्रामवासी
उम्मेदाबाद बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि, उम्मेदाबाद, तहसील-जालोर, जिला-जालोर

'बैकडेट' का खेल: डिजिटल क्रांति के दावों के बीच प्रशासनिक शुचिता तार-तार

यद्यपि वर्तमान समय में राजस्थान का सहकारिता विभाग अपनी तथाकथित 'डिजिटल क्रांति' के ढोल अतिशय ऊंचे स्वर में पीट रहा है, तथापि धरातल पर उसकी प्रशासनिक शुचिता पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो चुकी है। पैक्स-लैम्पस के कंप्यूटरीकरण का भ्रामक दावा जिस प्रकार फाइलों को ऑनलाइन करने की घोषित वकालत करता है, वह केवल एक प्रशासनिक मृगतृष्णा प्रतीत होती है। वास्तविकता यह है कि विभागीय अधिकारियों ने अपनी स्वार्थ-प्रेरित दृष्टि पर 'ऑफलाइन' विसंगतियों का ऐसा अभेद्य आवरण चढ़ा लिया है, जिसके सम्मुख न तो वैधानिक नियम टिक पा रहे हैं, न शासकीय नीति-निर्देश और न ही प्रशासनिक मर्यादाओं की न्यूनतम गरिमा शेष बची है। तत्पश्चात, जैसे ही स्थानांतरणों पर राजकीय प्रतिबंध की घोषणा हुई, वैसे ही महकमे में एक अभूतपूर्व एवं अवांछित आपाधापी व्याप्त हो गई। वहाँ 'राजकाज' पोर्टल नितांत मूकदर्शक और एक निष्प्राण शो-पीस बनकर रह गया। जब 10 जुलाई की रात्रि को वैधानिक आदेशों की सीमाएं संकुचित हुईं, तब विभाग के कतिपय नीति-निर्धारकों ने नेपथ्य से 'बैकडेट' (पूर्व-दिनांकित) का वह कपटपूर्ण खेल प्रारंभ किया, जो किसी काल्पनिक चलचित्र की पटकथा से भी अधिक विस्मयकारी और निंदनीय है। प्रतिबंध लागू होने के दो दिवस उपरांत अवांछित रूप से पिछली तारीखों में जारी किए गए स्थानांतरण आदेश स्पष्टतः प्रमाणित करते हैं कि यहाँ संस्थागत व्यवस्था से कहीं अधिक प्रभावी 'फाइलों की अनैतिक जुगाड़' सिद्ध हो रही है। वस्तुतः, जो सहकारी आंदोलन कभी मरुधरा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अक्षय आधार-स्तंभ माना जाता था, वह आज अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप और स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति के भंवर में बुरी तरह फंसा हुआ है। हालिया क्रम में, मूल स्थानांतरण सूची में जिस प्रकार द्रुत गति से विरूपण किया गया, वह संपूर्ण महकमे की पारदर्शिता पर एक अमिट प्रश्नचिह्न अंकित करता है। विधिक व्यवस्था यह है कि जो कैडर जिस पद हेतु पूर्व-निर्धारित है, वहाँ उसी पात्रता के अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्यतः होनी चाहिए, परंतु संप्रति संपूर्ण तंत्र केवल व्यक्तिगत सुविधा और राजनीतिक संरक्षणवाद के अधीन पूर्णरूपेण संचालित हो रहा है। यही नहीं, संस्थागत अराजकता का चरम उदाहरण तब परिलक्षित होता है, जब नाबार्ड एवं कृषि मंत्रालय द्वारा दो बार पुरस्कृत उत्कृष्ट केंद्रीय सहकारी बैंक में उप-रजिस्ट्रार के कैडर-अनुरूप पद पर अपेक्षाकृत कनिष्ठ, सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी को बलपूर्वक प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह कृत्य उक्त गौरवशाली संस्था के प्रशासनिक ढांचे पर सीधा आघात है। इसके अतिरिक्त, चिंताजनक पक्ष यह है कि जिस योग्य संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी को पूर्व में केंद्रीय सहकारी बैंक के उच्च पद प्रबंध निदेशक पर न्यायसंगत रूप से स्थानांतरित किया गया था, उन्हें बाद में कतिपय अदृश्य दबावों के चलते एक सामान्य यूनिट में उप-रजिस्ट्रार के पद पर पदावनत सदृश पदस्थ कर दिया गया। विभाग, ऊपरी तौर पर 'फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया' का पूर्ण निष्ठा से पालन करता हुआ अवश्य परिलक्षित हुआ, किंतु आंतरिक 'पहुंच' और 'संरक्षणवाद' की प्रवृत्तियां इस बार भी विभाग की घोषित तबादला नीति पर पूर्णतः हावी हो गईं। इसी के परिणामस्वरूप, जिस संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी को उक्त बैंक में पूर्व से आसीन 'पहुंचधारी अधिकारी' के स्थान पर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था, उस संयुक्त रजिस्ट्रार को पुनः उसी उप-रजिस्ट्रार के पद पर (अर्थात् उसी स्थान पर जहाँ पहुंचधारी अधिकारी का पूर्व में स्थानांतरण हुआ था) स्थानांतरित कर दिया गया, और उस रसूखदार 'पहुंचधारी अधिकारी' का स्थानांतरण आदेश 'बैकडेट' में पूर्णतः निरस्त कर दिया गया। विभागीय आंतरिक सूत्रों का प्रामाणिक रूप से कहना है कि जिस विशिष्ट अधिकारी के स्थानांतरण आदेश को इस प्रकार नियम विरुद्ध निरस्त किया गया, उनका दीर्घ सेवाकाल मुख्यतः जोधपुर खंड में व्यतीत हुआ है, तथा उनके विरुद्ध पूर्व में विभिन्न गंभीर विभागीय जाँचें निरंतर विचाराधीन रही हैं और उन्हें पूर्व में 16 सीसीए के तहत दंडनीय आरोप पत्र (चार्जशीट) भी प्राप्त हो चुके हैं। इसके विपरीत, संस्थागत विसंगति और प्रशासनिक पक्षपात की पराकाष्ठा वहाँ दृष्टिगोचर होती है, जहाँ पाली एवं राजसमंद जिलों में वित्तीय अथवा प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर मामलों में अकाट्य रूप से दोषी पाए जाने के उपरांत भी, एक अन्य दागी अधिकारी को विगत एक वर्ष से जालौर केंद्रीय सहकारी बैंक में 'अधिशाषी अधिकारी' जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नीति-निर्धारिक पद पर अवांछित रूप से यथावत आसीन रखा गया है।" सहकारिता का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है, किंतु यह वर्तमान परंपरा-विरोधी ऑफलाइन मुहिम इसके मूल सिद्धांतों को गंभीरता से धूमिल कर रही है। सहकारिता जगत अब व्यथित होकर यह यक्ष प्रश्न पूछ रहा है कि आखिरकार कब तक कैडर नीति की ऐसी अवहेलना होती रहेगी? क्या शासन इस प्रशासनिक कदाचार का संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध कठोर जवाबदेही सुनिश्चित करने का साहस दिखाएगा?

स्वायत्त शासी संस्थाओं का प्रशासनिक अधिग्रहण एवं निर्वाचन का संकट

-प्रकाश वैष्णव
लेखक स्तंभकार, संपादक एवं सहकार चिंतक हैं।

"राजस्थान की सहकारी संस्थाओं में एक दशक से चुनाव न होने के कारण लोकतांत्रिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इन संस्थाओं पर नौकरशाही और प्रशासकों का कब्जा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो गई है। सहकारिता को पुनर्जीवित करने के लिए तुरंत पारदर्शी चुनाव कराने की आवश्यकता है।"

राजस्थान के ग्रामीण, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को समृद्ध करने वाली स्वायत्त सहकारी संस्थाएं वर्तमान में गम्भीर प्रशासनिक उदासीनता, नीतिगत विसंगतियों और लोकतान्त्रिक शून्यता के दौर से गुजर रही हैं। सहकारिता आन्दोलन का मूल दर्शन एवं सिद्धान्त उसकी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में निहित होता है, जहाँ प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के प्रतिनिधित्व से निर्वाचित संचालक मण्डल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक ही संस्था के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। किन्तु धरातल पर स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है, जहाँ राज्य में दलगत राजनीति से परे रहकर 'सहकारिता से समृद्धि' और 'सहकारिता से स्वावलम्बन' के राष्ट्रीय संकल्पों को साकार करने की दुहाई तो दी जाती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रदेश की शीर्ष से लेकर प्राथमिक स्तर की सहकारी संस्थाओं में पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से चुनाव न कराकर लोकतान्त्रिक मूल्यों की खुली अवहेलना की जा रही है। सहकारी समितियों के निर्वाचन समय पर सम्पन्न न होने के कारण राज्य में सहकारी नेतृत्व एवं कॉर्पोरेट लीडरशिप का भीषण अकाल पड़ गया है, तथा लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित मण्डलों के अभाव में इन स्वायत्त संस्थाओं की कमान पूर्णतः नौकरशाही और सरकारी प्रशासकों के हाथों में सौंप दी गई है। वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रदेश की 23 शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं तथा 25 केन्द्रीय सहकारी बैंकों सहित 17 भूमि विकास बैंकों में चेयरमैन का पद निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय प्रशासनिक अधिकारियों को बतौर प्रशासक नियुक्त कर संचालित किया जा रहा है। भूमि विकास बैंकों के चेयरमैन और सीसीबी के डायरेक्टर पद, जो राजनीतिक और नीतिगत दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वे नौकरशाही के चंगुल में फँसकर रह गए हैं, जिससे इन संस्थाओं में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इस प्रशासनिक अधिराज के कारण राज्य में 1558 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पिछले 1 दशक से निर्वाचित नेतृत्व से विहीन हैं, तथा सामान्यतः प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर गठित होने वाली 73 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां भी वर्तमान में पूरी तरह प्रशासकों के अधीन कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही, वित्तीय रीढ़ माने जाने वाले 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक और दीर्घकालीन कृषि ऋण ढांचा सम्भालने वाले 19 भूमि विकास सहकारी बैंक भी निर्वाचित मण्डल के अभाव में नीतिगत पंगुता का शिकार हो चुके हैं। सहकारिता क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास की यह कहानी केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की 10 शीर्षस्थ और नीति-निर्धारक सहकारी संस्थाएं भी विगत कई वर्षों से तदर्थ व्यवस्था और सरकारी प्रशासकों के सहारे चल रही हैं। इन शीर्ष संस्थाओं में निर्वाचित बोर्ड के स्थान पर दशकों पुराने मनोनयन अथवा प्रशासनिक नियुक्तियों का अन्तहीन सिलसिला जारी है, जिसके तहत अपेक्स बैंक में वर्ष 2016 से, राजफेड में वर्ष 1995 से, कॉनफेड में वर्ष 2014 से तथा एसएलडीबी में वर्ष 2015 से चुनाव लम्बित चल रहे हैं।

इसी प्रकार, सहकारी मुद्रणालय में वर्ष 1997 से, सहकारी संघ में वर्ष 2016 से, अनुजा निगम में वर्ष 1999 से तथा तिलम संघ में वर्ष 2005 से लगातार अन्तरिम व्यवस्था के रूप में प्रशासक ही नियुक्त हैं। विडंबना की पराकाष्ठा यह है कि आवासन संघ और राजस्थान राज्य क्षेत्रीय जनजाति सहकारी विकास संघ, उदयपुर जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में तो स्थापना के बाद से अब तक एक बार भी लोकतान्त्रिक चुनाव नहीं हुए हैं और वहाँ स्थापना काल से ही सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल के माध्यम से तदर्थवाद का पोषण किया जा रहा है। सहकारी अधिनियम के तहत सहकारी संस्थाओं में भी निर्वाचित बोर्ड का होना उतना ही अनिवार्य और संवैधानिक है, जितना कि राज्य की विधान सभा और देश की संसद के लिए निर्वाचित सरकारों का होना अनिवार्य माना जाता है। नियमित चुनाव न होने से न केवल संस्थाओं का लोकतान्त्रिक ढांचा चरमरा गया है, बल्कि हितधारक सदस्यों और किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा भी असम्भव हो गई है, क्योंकि जब तक सहकारी आन्दोलन के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और प्रकल्पों में सहकारिता से जुड़े वास्तविक हितधारक सदस्यों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों का नेतृत्व एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक सहकारिता आन्दोलन में यह नीतिगत रिक्तता बनी रहेगी। नौकरशाही के इस अनियन्त्रित हस्तक्षेप के कारण संस्थाएँ आम किसानों और सम्बद्ध सदस्यों के प्रति जवाबदेह होने के बजाय केवल सरकारी आदेशों की तामीर करने वाले विभागों में तब्दील हो गई हैं। अतः यदि राज्य में सहकारिता आन्दोलन को पुनर्जीवित करना है और स्वायत्तता के वास्तविक सिद्धान्तों को बहाल करना है, तो सरकार को अविलम्ब तदर्थवाद की इस नीति का परित्याग करना होगा और अधिकारियों को प्रशासक लगाकर सहकारी आन्दोलन की आत्मा को कुचलने की व्यवस्था को तत्काल बन्द करना होगा। राज्य सरकार को एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर प्राथमिक स्तर से लेकर राज्य स्तर की सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अविलम्ब पारदर्शी एवं निष्पक्ष लोकतान्त्रिक चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है, जिससे सदस्यों में से ही एक प्रतिबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह नेतृत्व का निर्माण होगा, जो राजस्थान के कृषि और ग्रामीण विकास को एक नई व सुदृढ़ दिशा प्रदान कर सकेगा।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

बाड़मेर सीसीबी में एमडी की नियुक्ति: 'पुराने अनुभव' से 'नई उम्मीदें', क्या नियमों की डगर पर लौटेगी सहकारिता?

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर। जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक में लंबे समय से रिक्त चल रहे प्रबंध निदेशक के पद पर राज्य सहकारिता सेवा के संयुक्त रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार की नियुक्ति ने सहकारिता जगत में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बैंक पिछले कुछ समय से गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में अनियमितताओं और तत्कालीन एमडी के निलंबन जैसे संकटों से जूझ रहा था। जोधपुर सीसीबी के एमडी के पास चल रहे अतिरिक्त कार्यभार से राहत देते हुए सरकार ने अब पूर्णकालिक तैनाती कर दी है। हालांकि यह नियुक्ति 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंडों को पूरा करती है, लेकिन इस तैनाती के साथ ही अतीत के कुछ प्रशासनिक पन्ने भी फिर से चर्चा में आ गए हैं। सहकारिता से जुड़े आमजन और किसान अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि नई नियुक्ति के बाद बैंक की कार्यप्रणाली में अनुशासन और पारदर्शिता आएगी। बैंक प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता इन पुराने विवादों की निष्पक्ष समीक्षा करना और उन्हें नियमों के दायरे में लाना होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नई कमान पिछले अनुभवों से सीख लेकर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाती है, तो बैंक की बिगड़ी साख को सुधारा जा सकता है। बाड़मेर जिले के किसानों के लिए सीसीबी केवल एक बैंक नहीं, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। ऐसे में, इस पद पर बैठा अधिकारी न केवल एक प्रशासनिक पदाधिकारी है, बल्कि वह लाखों किसानों के भरोसे का संरक्षक भी है। अब देखना यह होगा कि इस नियुक्ति के बाद बैंक का भविष्य नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है या फिर पुराने विवादों की परछाई में ही उलझा रहता है।

अतीत के वे पन्ने, जो अब नई चुनौती बने

इस नियुक्ति का एक पक्ष वह भी है जिसे सुधारना नई कमान के लिए बड़ी चुनौती होगी। पिछले कार्यकाल के दौरान हुए कुछ निर्णयों ने प्रशासनिक गलियारों में सवाल खड़े किए थे:

111 कर्मचारियों का स्थाईकरण	अगस्त-अक्टूबर 2022 के दौरान जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पैक्स स्तर पर करीब 111 कर्मचारियों को स्थाई किया गया था। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद यह मामला अब विवादों में है, क्योंकि उप रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2005 के बाद से पैक्स स्तर पर किसी भी कार्मिक प्रस्ताव का अनुमोदन या पुष्टि नहीं की गई थी। ऐसे में, इस प्रक्रिया की वैधता पर उठ रहे सवाल बैंक प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती हैं।
बाजरा खरीद में पर्यवेक्षण की विफलता	पिछले समय में जिले में पैक्स कार्यक्षेत्र में बाजरा खरीद के दौरान हुई गड़बड़ियों ने विभाग की साख को धक्का पहुंचाया था। इस मामले में धारा-55 के तहत 75 पैक्स कार्मिकों का दायित्व निर्धारित किया गया था। यह घटनाक्रम उस समय के विभागीय पर्यवेक्षण (सुपरविजन) की खामियों को उजागर करता है।

अब यह देखना नई कमान के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि वह इन अधूरे अध्यायों को कैसे पूरा करते हैं और सहकारिता के इस महत्वपूर्ण संस्थान को नई दिशा देकर तुंस्त और पारदर्शी प्रशासन स्थापित कर पाते हैं।

जिले की सहकारिता के 'जानकार' हैं जितेंद्र कुमार

नई जिम्मेदारी संभालने वाले सहकारी सेवा के संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी जितेंद्र कुमार का बाड़मेर जिले से पुराना नाता रहा है। सहायक रजिस्ट्रार के रूप में करियर की शुरुआत से लेकर बालोतरा पीएलडीबी में सचिव और बाद में जिला स्तरीय उप रजिस्ट्रार कार्यालय तक की अहम भूमिकाओं के चलते उन्हें जिले की सहकारी नब्ज का गहरा ज्ञान है। वे वर्ष 2021 से 2024 तक इसी बैंक में एमडी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि इतने लंबे समय तक एक ही जिले और एक ही पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को पुनः उसी पद पर पदस्थापित करना अपने आप में एक अनूठा कदम है।

सहकारिता से आर्थिकी को गति

एस. एस. यादव एमडी कृभको
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

भारत की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला है। भारत का सहकारी तंत्र केवल कृषि तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तीकरण, दुग्ध उत्पादन, लघु उद्योग और वित्तीय समावेशन का भी एक मजबूत माध्यम है। विकसित भारत के निर्माण में यह माडल सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहकारिता का ढांचा ग्रामीण भारत की वास्तविक आवश्यकताओं के सबसे निकट है। कुल मिलाकर भारत में सहकारिता आंदोलन केवल आर्थिक प्रगति का माडल नहीं, बल्कि साझेदारी सहभागिता और सामूहिक प्रगति का आधार रहा है। इसी भावना को साकार करने के उद्देश्य से 17 अप्रैल, 1980 को कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) की स्थापना की गई। उस समय देश हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादन में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उर्वरकों की बढ़ती मांग और समय पर पर्याप्त उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी। इसे देखते हुए सहकारी समितियों की भागीदारी से कृभको का गठन किया गया, ताकि किसानों तक उर्वरकों की सस्ती और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित हो सके। पिछले 46 वर्षों में इस संगठन ने न केवल अपने मूल उद्देश्यों को पूरा किया है, बल्कि सहकारिता के क्षेत्र में एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज यह देश के अग्रणी सहकारी उर्वरक संगठनों में शामिल है व लाखों किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। कृभको ने केवल रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की है, बल्कि संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक खेती, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग और जल संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करने का भी कार्य किया है। आज कृषि केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, गुणवत्ता, लागत और पर्यावरणीय संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण संरक्षण: आज जब पूरी दुनिया टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है, इस संगठन ने कृषि में हरित तकनीकों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। जैविक उत्पादों का विस्तार, डिजिटल कृषि सेवाएं, मोबाइल आधारित कृषि परामर्श जैसे कदम भविष्य की कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस संगठन ने डिजिटल ट्रांसफार्मेशन को अपनी कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा बनाया है। किसानों को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से प्रशिक्षण, सलाह और बाजार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे किसान अधिक जागरूक और तकनीक सक्षम बने हैं। कोरोना महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इस संगठन ने किसानों तक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाया। आयात पर निर्भरता में कमी हाल में पश्चिम एशिया संकट की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं ने भारत के लिए उर्वरकों, विशेषकर राक फास्फेट, पोटाश और प्राकृतिक गैस आधारित कच्चे माल के आयात को प्रभावित किया है। ऐसे कठिन समय में इस संगठन ने अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए घरेलू स्तर पर यूरिया उत्पादन को स्थिर रखा है और वैकल्पिक वैश्विक बाजारों से

कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। साथ ही, जैविक विकल्पों को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता कम करने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। यह कदम संकट के समय किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। भारत आज वैश्विक मंच पर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हमारा विश्वास है कि यदि किसान मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। यदि सहकारिता मजबूत होगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का किसान आत्मनिर्भर, तकनीक संपन्न और समृद्ध होगा। कृभको इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, नवाचार और समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारिता की शक्ति, किसानों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शी नीतियां मिलकर भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मिला सहकारिता मंत्री से; एचआर पॉलिसी जल्द लागू करने का मिला भरोसा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

एचआर पॉलिसी का इंतजार लंबा

संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि सहकार सप्ताह के दौरान विभाग ने नाबार्ड की एचआर पॉलिसी जारी करने की घोषणा की थी। हालांकि, घोषणा के काफी समय बीत जाने के बाद भी इस नीति का विमोचन नहीं हुआ है, जिससे कार्मिकों में भारी रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि यह नीति उनकी सेवा सुरक्षा और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए बेहद जरूरी है।

जयपुर। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों और विभागीय समझौतों के क्रियान्वयन की मांग को लेकर विभाग पर दबाव बढ़ा दिया है। समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों की उपेक्षा पर गहरी नाराजगी जताई है और मामले का तत्काल समाधान करने की मांग की है समिति के मदन मेनारिया, देवेन्द्र सैदावत, टिकेंद्र कटारा, सत्यनारायण तिवारी, नरपतसिंह चारण और जितेन्द्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि विभागीय स्तर पर हुए पूर्व समझौतों को मूर्त रूप देते हुए इन मांगों को शीघ्र लागू किया जाए समिति ने आरोप लगाया कि राजस्थान में पैक्स-लैम्पस स्तर पर व्यवस्थापकों के कई पद रिक्त होने के बावजूद कर्मचारी केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में राज्य को देश में अव्वल बनाए हुए हैं। इसके बावजूद, उन्हें नीतिगत सुरक्षा से वंचित रखा गया है। समिति के अनुसार, वर्तमान ढांचा अव्यावहारिक है, जिससे सहकारी आंदोलन कमजोर हो रहा है अपनी मांगों को लेकर संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देने के पश्चात सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहरसिंह बेढम से मुलाकात की। इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने प्रतिनिधिमंडल को लंबित 'एचआर पॉलिसी' को जल्द से जल्द लागू करने का आश्वासन दिया है।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

दी पाली सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
द्वारा आयोजित सहकार सप्ताह (वर्ष 2026-27) के अवसर पर,
श्री जब्बाराम पटेल (व्यवस्थापक, पैक्स-बिठू एवं सिणगारी)
को सहकारिता के क्षेत्र में उनके अत्यंत उल्लेखनीय एवं सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किए जाने पर
हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं
:::: शुभेच्छु ::::
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक बोर्ड सदस्य गण, पैक्स स्टाफ बिठू एवं सिणगारी बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि, बिठू-सिणगारी, जिला-पाली

पैक्स पर थोपी जा रही खाद की 'टैगिंग', सहकार नेता आमेरा ने इफ्को-कृभको प्रबंधन को घेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

समितियों को नुकसान: कृषि विभाग की अनुमति न होने से किसान उत्पाद नहीं खरीद रहे, जिससे समितियों को नुकसान है।

नीतियों में टकराव: नैनो यूरिया को लेकर केंद्र के प्रोत्साहन और राज्य की अनुमति न होने से विरोधाभास बना हुआ है।

जयपुर। राज्य की सहकारी साख समितियों (पैक्स) पर यूरिया व अन्य खाद के साथ जबरन उत्पादों की 'टैगिंग' थोपे जाने का मुद्दा गरमा गया है। सहकारी साख समितियाँ एम्पलाईज यूनियन के प्रान्तीय अध्यक्ष सूरज भान सिंह आमेरा ने कृभको और इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधकों से मुलाकात कर इस बाध्यकारी बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। आमेरा ने कृभको के मुख्य राज्य विपणन प्रबंधक रामजी लाल शर्मा एवं इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक पृथ्वी राज सिहाग को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि खाद के साथ अन्य अनावश्यक उत्पाद थोपे जाने से समितियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है आमेरा ने बताया कि राज्य सरकार के कृषि विभाग ने इन टैगिंग उत्पादों को लेकर कोई अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते किसान इन्हें खरीदने से साफ इनकार कर देते हैं। इससे पैक्स कर्मचारियों और किसानों के बीच अनावश्यक विवाद और तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक निर्देश नहीं मिलते, तब तक किसानों पर कोई भी उत्पाद जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए।

केंद्र और राज्य की नीतियों में टकराव

इफ्को प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार नैनो यूरिया को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखे गए हैं। वहीं दूसरी ओर, राज्य के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने से नीतिगत विरोधाभास पैदा हो गया है। सहकार नेता आमेरा ने दो टूक कहा कि इस भ्रम की स्थिति के कारण समितियों का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि न तो समितियों को आर्थिक नुकसान हो और न ही किसानों को परेशानी का सामना करना पड़े।

राजस्थान विधानसभा में खुलासा

अपेक्स बैंक में M.Sc. की फर्जी डिग्री से लाभ उठाने वाले 41 कार्मिक चिह्नित, वेतन वृद्धि निरस्त

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) में MMC (आई.टी.) फर्जी डिग्रियों के सहारे विशेष वेतन वृद्धि का लाभ उठाने का मामला सामने आया है। बैंक के 53 कार्मिकों ने एम.एस.सी. (आई.टी.) व समकक्ष डिग्रियों के आधार पर दो विशेष वेतन वृद्धियों का लाभ लिया था। जांच के दौरान इन डिग्रियों के फर्जी पाए जाने पर बैंक प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 41 कार्मिकों की वेतन वृद्धि निरस्त कर दी है और उनसे भुगतान की गई राशि मय ब्याज वसूलने के निर्देश दिए हैं, दरअसल, राजस्थान विधानसभा में विधायक कालीचरण सराफ द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में विभाग के लिखित जवाब मे खुलासा हुआ सदन में पेश किए गए विवरण के अनुसार, बैंक के 53 कार्मिकों ने एम.एस.सी. (आई.टी.) या इसके समकक्ष योग्यता दिखाकर वेतन वृद्धि का लाभ लिया था। इन डिग्रियों की वैधता की जांच के दौरान बैंक अधिकारियों ने इसे नियम विरुद्ध पाया जांच प्रक्रिया के दौरान, संबंधित 10 कार्मिकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली और जांच पर स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त कर लिया। वहीं, 2 कार्मिकों की डिग्रियां जांच में मान्य पाई गईं।
शेष 41 कार्मिकों की डिग्रियां जांच में सही नहीं निकलीं तथा बैंक प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इन 41 कार्मिकों की सेवा पुस्तिका से एम.एस.सी. (आई.टी.) डिग्री को विलोपित (डिलीट) कर दिया है। इसके साथ ही, उन्हें भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी देते हुए कारण बताओ पत्र भी जारी किए गए हैं।

नाबार्ड स्थापना दिवस: प्रागपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को मिला 'राज्य स्तरीय अवार्ड'

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज राजस्थान स्टेट नाबार्ड कार्यालय में आयोजित भव्य राज्य स्तरीय समारोह में कोटपूतली-बहरोड़ जिले की प्रागपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को सम्मानित किया गया। समिति को यह प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय अवार्ड 'पैक्स एक्सीलरेटर प्रोग्राम' के अंतर्गत उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया।समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास रहे। कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति में डॉ. सुमित शर्मा शासन सचिव व पंजीयक सहकारिता विभाग नाबार्ड उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय निदेशक, नाबार्ड राजस्थान मुख्य महाप्रबंधक डॉ. आर. रवि बाबू, राजस्थान ग्रामीण बैंक चेयरमैन और भारतीय स्टेट बैंक सीजीएम (राजस्थान) उपस्थित थे, नाबार्ड की ओर से यह सम्मान समिति के चेयरमैन उपेन्द्र सिंह शेखावत और कैलाश चन्द स्वामी ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि समिति को यह पुरस्कार कृषकों की आय में वृद्धि, सामूहिक विपणन, मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नाबार्ड द्वारा समिति की इन उपलब्धियों की सराहना की गई और भविष्य में भी उनके सतत विकास की कामना की गई है।

राइसेम में संवाद कार्यक्रम आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 'सहकार सप्ताह' के तहत झालाना स्थित राइसेम संस्थान में राजस्थान राज्य सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता और पूर्व विशेषाधिकारी श्री पंकज भानु सिंह गोगावत ने बताया कि 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025' का मुख्य उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीक, पेपरलेस कार्य और डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करना है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए किसानों की वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने हेतु तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं (ऑर्गेनिक, एक्सपोर्ट और बीज) का गठन किया गया है। नई नीति विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार और समावेशी विकास पर केंद्रित है। राइसेम निदेशक संजय पाठक ने पैक्स डिजिटलीकरण अभियान को ग्रामीण स्तर पर मजबूत संस्थागत व्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया। इसी कड़ी में एस.एल.डी.बी. जयपुर में प्रशासक संदीप खण्डेलवाल की अध्यक्षता में 'सहकार संवाद दिवस' मनाया गया। प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद ने दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना की उपलब्धियों की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभा में बैंकों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, ऋण लागत में कमी और एनपीए घटाने से जुड़ी आगामी पांच वर्षीय कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।

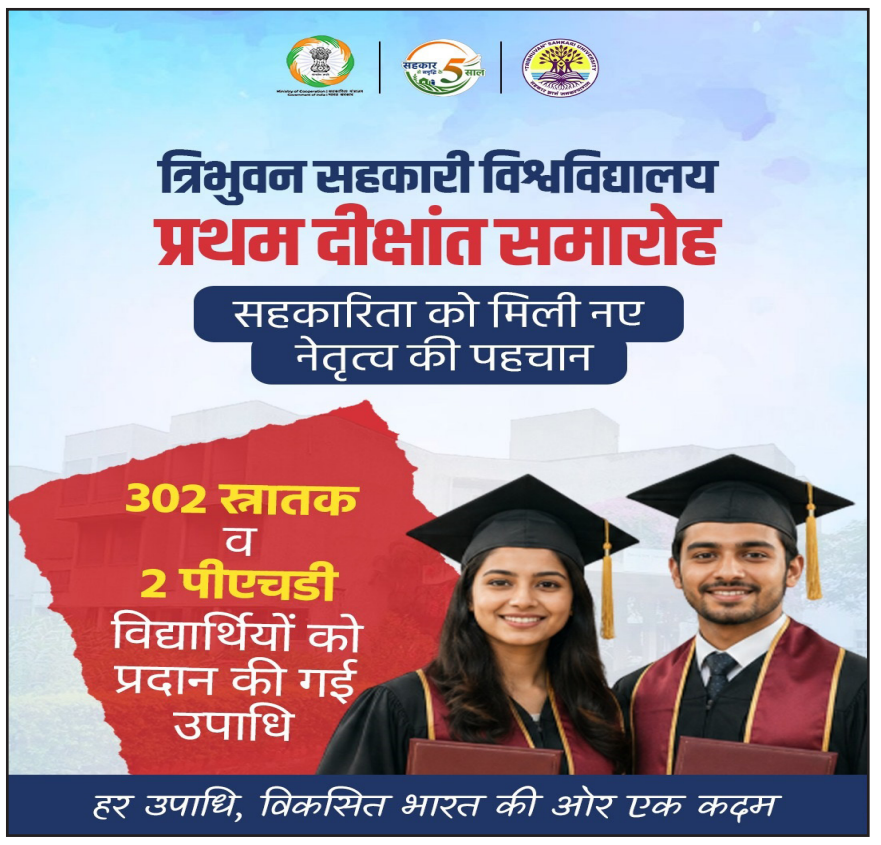

सहकारी समितियों में नियमों को ताक पर रख बांटे जा रहे पद और लाखों का वेतन, न जमानत ली और न ही सिक्योरिटी: ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सूची से बाहर करने के बाद भी वेतन भुगतान की बात आई सामने

सहकारी समितियों में तय नियमों को दरकिनार कर भत्तों और वेतन में की गई बढ़ोतरी का विवरण भी ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, डोली कल्ला जीएसएस के व्यवस्थापक खुशालाराम की शैक्षणिक योग्यता वर्ष 2022 में पूर्ण नहीं होने के कारण जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी द्वारा उनके स्थाईकरण की पत्रावली और आवेदन पत्र को स्थाईकरण की सूची से बाहर कर दिया गया था। इसके बावजूद, ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्हें व्यवस्थापक पद पर कार्यरत बताते हुए 6 लाख 31 हजार रुपये का भारी-भरकम वार्षिक वेतन भुगतान किया गया है। दूसरी ओर, कल्याणपुर जीएसएस की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, व्यवस्थापक खीमाराम का वेतन वर्ष 2017-18 में 1 लाख 80 हजार रुपये था, जिसे वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट में 4 लाख 95 हजार रुपये दर्शाया गया है। इसके साथ ही उन्हें पीएफ राशि के तौर पर 1 लाख 92 हजार रुपये दिए गए हैं और 18 लाख रुपये का ग्रेच्युटी कोष बनाया गया है। इसी तरह पारलु समिति में भी व्यवस्थापक को 3 लाख 24 हजार 912 रुपये वेतन भुगतान करने के साथ ही 7 लाख रुपये का ग्रेच्युटी कोष और 4 लाख रुपये का पीएफ कोष प्रावधानित करने की बात ऑडिट रिपोर्ट में कही गई है, जो कि निर्धारित नियमों के विपरीत वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है।

बालोतरा । जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (जीएसएस) में नियुक्तियों, जमानत नामा (बॉण्ड) और व्यक्तिगत प्रतिभूति (पर्सनल सिक्योरिटी) को लेकर निर्धारित नियमों की पालना नहीं होने की बात सामने आई है। सहकारिता विभाग के स्पष्ट आदेशों के अनुसार 10 जुलाई 2017 के बाद से जीएसएस में व्यवस्थापकों की नई नियुक्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद, ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कई समितियों में नियमों के विपरीत जाकर नियुक्तियां किए जाने और बिना किसी वित्तीय सुरक्षा (जमानत नामा व प्रतिभूति) के ही कर्मचारियों को लाखों रुपये के वेतन और फंड का भुगतान करने की कमियां उजागर हुई हैं। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आए पारलु, करमावास, कल्याणपुर और डोली कल्ला समितियों के आंकड़े दर्शाते हैं कि कई जगह निर्धारित मापदंड पूरे नहीं होने के बावजूद कार्मिकों को लाखों का भुगतान किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिले की एक भी ग्राम सेवा सहकारी समिति का वेतन एवं नियुक्ति प्रस्ताव उप रजिस्ट्रार कार्यालय की चौखट तक पहुंचा ही नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बाड़मेर द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005 के पश्चात उप रजिस्ट्रार कार्यालय स्तर से समिति में सेल्समैन या सहायक व्यवस्थापक रखे जाने संबंधी किसी भी प्रस्ताव का प्रमाणिकरण नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, वर्ष 2005 से पूर्व की पत्रावलियों की वीडिंग (रिकॉर्ड नष्ट) किए जाने के कारण व्यवस्थापकों के प्रस्ताव प्रमाणिकरण के संबंध में कोई रिकॉर्ड भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

बिना वित्तीय सुरक्षा और गायब दस्तावेजों के सहारे व्यवस्था संचालन का ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वित्तीय लेन-देन की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज जमानत नामा और व्यक्तिगत प्रतिभूति माने जाते हैं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पारलु, करमावास, कल्याणपुर और डोली कल्ला चारों ही समितियों में कार्यरत जिम्मेदार कार्मिकों से यह प्रतिभूति नहीं ली गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, पारलु जीएसएस में 2017 के बाद नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध होने के बावजूद विक्रमसिंह राजपुरोहित को व्यवस्थापक पद पर कार्यरत बताया गया है और समिति व बैंक स्तर से नियुक्ति होने का हवाला दिया गया है। इसी तरह करमावास समिति की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012-13 में महज 60 हजार रुपये सालाना वेतन पाने वाले सहायक व्यवस्थापक श्रवणपूरी को बाद में व्यवस्थापक पद का चार्ज दिया गया और वर्ष 2024-25 तक उनका वेतन बढ़ाकर 4 लाख 40 हजार रुपये कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक (बीए) बताई गई है, लेकिन इससे संबंधित पत्र/दस्तावेज समिति में उपलब्ध नहीं होने की जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, बिना किसी वित्तीय जमानत और दस्तावेजों के इस तरह पदों पर कार्य करने व वेतन भुगतान की अनियमितता सामने आई है।

मारवाड़ का मित्र
जुड़े और पढ़ें हर पल की खबर
मारवाड़ का मित्र
facebook.com/marwarkamitra
visit,Like and share

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/-☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) बुधवार, 15 जुलाई 2026
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
MSME Reg. - UDYAM-RJ-19-0033346

सहकारिता से समृद्धि के दावे खोखले, पैक्स कर्मियों को न वेतन न पेंशन: आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

श्रीगंगानगर। प्रदेश के सहकारी पैक्स कर्मियों की दयनीय स्थिति और सहकारी तंत्र की विसंगतियों को लेकर सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने सरकार और सहकारी विभाग पर तीखा हमला बोला है धान मंडी स्थित ट्रेडर्स एसोसिएशन के विशाल सभागार में आयोजित पैक्स कर्मियों के भव्य जिला सम्मेलन में आमेरा ने दो-टूक कहा कि जब तक पैक्स कर्मी का पेट खाली रहेगा और उसका भविष्य असुरक्षित रहेगा, तब तक 'सहकार से समृद्धि' का नारा केवल एक कागजी सपना बनकर रह जाएगा तथा आमेरा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए गहरी चिंता जताई कि देश आज आजादी का अमृत काल मना रहा है, लेकिन प्रदेश

के सहकारी पैक्स कर्मियों के लिए यह काल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उन्होंने कहा, "यह विडंबना ही है कि त्रि-स्तरीय सहकारी साख ढांचे में जहां बैंक करोड़ों रुपये का आयकर सरकार को दे रहे हैं, वहीं उस व्यवस्था के अभिन्न अंग—पैक्स कर्मी—दो जून की रोटी के लिए मोहताज हैं।" आमेरा ने मंच से सरकार और सहकारिता विभाग से सवाल किया कि आखिर ऐसी व्यवस्था का क्या औचित्य है, जहां कर्मी को न तो नियमित वेतन मिलता है, न ही पीएफ कटौती, चिकित्सा सुविधा, ग्रेच्युटी या उपार्जित अवकाश जैसी बुनियादी सहूलियतें हासिल हैं। उन्होंने इसे सहकारिता की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करार दिया और आमेरा ने अपने संबोधन के समापन पर सभी कर्मियों से आह्वान किया कि अनुशासित और मजबूत संगठन ही उनकी पीड़ा का अंतिम निवारण करेगा। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक प्रत्येक पैक्स कर्मी को सुरक्षित भविष्य और सम्मानजनक वेतन नहीं मिल जाता।

अव्यवहारिक 'एम-पैक्स' और टुकड़ों में बंटवारा

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की सहकारी नवाचार पहल और तकनीकी क्रांति का स्वागत करते हुए आमेरा ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर पंचायत में 'कोई भी एक' सहकारी समिति खोलने का निर्णय लिया है, न कि हर पंचायत में जबरन नई 'एम-पैक्स' खोलने का। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्तरों पर मौजूदा पैक्स के टुकड़े-टुकड़े कर नई पैक्स बनाने की जो कवायद की जा रही है, वह अव्यवहारिक और आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। ऐसी मनमानीपूर्ण कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।

संगठन की मजबूती पर जोर

जिला अध्यक्ष प्रगट सिंह ने आमेरा का साफा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आमेरा के अनुभवी और ईमानदार नेतृत्व में ही पैक्स कर्मियों की पीड़ा का निवारण संभव है। सम्मेलन में वीरेंद्र यादव, राजकुमार वर्मा, रवि गोदारा, जसवंत पचार, सुखदीप सिंह संधू, जसविंदर सिंह बराड़, राम भक्त शर्मा, रमेश ढाँका (हनुमानगढ़) सहित पंजाब के पैक्स अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में आमेरा पर पूर्ण विश्वास जताते हुए बैंक कर्मियों की तर्ज पर पैक्स कर्मियों को सुविधाएं दिलाने का आह्वान किया।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

दी जालोर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
द्वारा आयोजित सहकार सप्ताह (वर्ष 2026-27) के अवसर पर,
श्री भागीरथसिंह (व्यवस्थापक, पैक्स-पावटा)
को सहकारिता के क्षेत्र में उनके अत्यंत उल्लेखनीय एवं सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किए जाने पर
हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं
:::: शुभेच्छु ::::
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक बोर्ड सदस्य गण
पैक्स स्टाफ एवं समस्त ग्रामवासी
पावटा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि, पावटा , तहसील-आहोर, जिला-जालोर

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में डीपीसी अनियमितताओं की जांच: जांच रिपोर्ट तैयार, खुलासा अभी बाकी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर। संभाग के विभिन्न जिलों में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंकों में अधिकारियो और कर्मचारियों की डीपीसी विभागीय पदोन्नति समिति के दौरान हुई कथित अनियमितताओं का मामला गरमाता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने जांच के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट तो तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं किया गया है मामले की शुरुआत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्रसिंह खीवंसर और अन्य विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायती पत्र से हुई थी। इस पत्र में जोधपुर संभाग के केंद्रीय सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की डीपीसी में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे इस शिकायत के बाद सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), प्रधान कार्यालय, जयपुर ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट का परीक्षण किया। इसके उपरांत राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के तहत विधिवत जांच के आदेश जारी किए गए। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पदोन्नति से जुड़े इस मामले में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए हैं और विभाग भविष्य में क्या कार्रवाई करता है।

अधिनियम की धारा 55 मे जांच अधिकारी की नियुक्ति

सहकारिता विभाग अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ जोधपुर,देवेन्द्र अमरावत ने इस मामले की जांच के लिए रामसुख, सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बिलाड़ा को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम अन्तर्गत धारा 55 मे जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जांच अधिकारी को तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार के कार्यकाल के दौरान हुई डीपीसी प्रक्रिया की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे हाल ही मे सहकार चिंतक एव पत्रकार प्रकाश वैष्णव ने इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस मामले की जानकारी मांगी थी। कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी विभाग जोधपुर द्वारा दिए गए जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट 22 जून 2026 को ही प्रस्तुत की जा चुकी है। हालाँकि, विभाग ने अभी तक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि जांच के परिणाम और अंतिम निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराना फिलहाल संभव नहीं है !

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

सहकारिता क्षेत्र में सीकर सीसीबी और निमोद एम-पैक्स का शानदार प्रदर्शन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

- सहकारिता रैंकिंग में सीकर जिला सहकारी बैंक प्रथम और बूंदी दूसरे स्थान पर रहा।
- एम-पैक्स श्रेणी में निमोद सहकारी समिति ने पहला स्थान हासिल किया।

जयपुर राजस्थान को सहकारिता के क्षेत्र में देश में सिरमौर बनाने की प्रतिबद्धता के साथ शासन सचिवालय के मंथन सभागार से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और एम-पैक्स के प्रदर्शन की गहन समीक्षा की बैठक में 'की परफोरमेंस इण्डीकेटर्स' के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन किया गया। इसमें सीकर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक ने 67.42 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, बूंदी सीसीबी दूसरे और जोधपुर सीसीबी तीसरे स्थान पर रही। एम-पैक्स श्रेणी में निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति ने 77.50 अंकों के साथ बाजी मारी, जबकि भीया समिति दूसरे और घाट का बराना समिति तीसरे स्थान पर रही डॉ. शर्मा ने बताया कि भविष्य में हर माह एम-पैक्स की रैंकिंग जारी की जाएगी, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत पैक्स की वित्तीय स्थिति, ऋण वितरण, ऑडिट अनुपालना और अकृषि गतिविधियों जैसे मानकों को आधार बनाया जाएगा। बैठक में सहकारिता की सफलता को रेखांकित करने वाली शॉर्ट फिल्मों और भगवानपुरा व नीमोद समितियों की प्रेरक कहानियों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान आयोजित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में 5 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता निभाई, जो सहकारी योजनाओं के प्रति बढ़ते जन-उत्साह को दर्शाती है।

सहकार से समृद्धि' का मंत्र

शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सहकारी बैंक और एम-पैक्स को आपसी समन्वय से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं—विशेषकर अन्न भंडारण योजना, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन और डोर-स्टेप बैंकिंग—का लाभ बिना भेदभाव अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। डॉ. शर्मा ने कार्मिकों को समयबद्धता और निष्ठा के साथ दायित्व निभाने के लिए प्रेरित किया।

जयपुर में पुस्तक 'राजस्थान में सहकारिता' का विमोचन; सहकारिता मंत्री दक ने सराहा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। अपेक्स बैंक सभागार में आयोजित कृषक सम्मान समारोह के दौरान सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. जयप्रकाश यादव द्वारा लिखित पुस्तक 'राजस्थान में सहकारिता' का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्री दक ने कहा कि यह पुस्तक सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देगी। उन्होंने इसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों और सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी और समय की मांग बताया। लेखक डॉ. जयप्रकाश यादव ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुस्तक का उद्देश्य राजस्थान में सहकारिता के इतिहास, विकास और वर्तमान परिदृश्य को एक स्थान पर संकलित कर पाठकों को प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

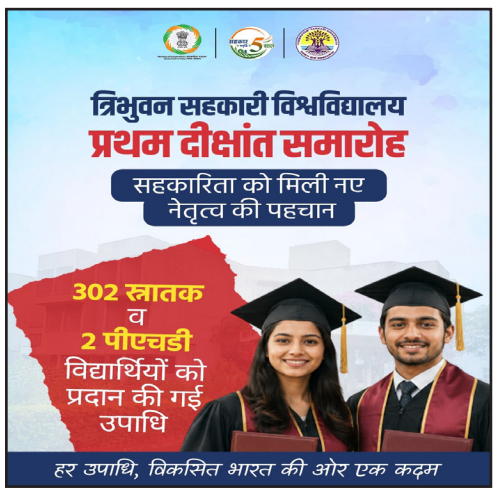

राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मान समारोह आयोजित; उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हुए सम्मानित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था मात्र नहीं है, बल्कि यह 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' के मूल सिद्धांत पर आधारित जनकल्याण की एक ऐसी सशक्त विचारधारा है, जिसके माध्यम से हम एकता, विश्वास और सामूहिक सहभागिता की शक्ति से हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं सहकारिता मंत्री, जिन्होंने प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की समर्पित कार्यशैली की सराहना की, ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारी टीम के अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता का ही सुखद परिणाम है कि आज राजस्थान 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में पूरे देश के अग्रणी राज्यों में अपनी एक विशिष्ट

पहचान स्थापित कर चुका है। इस भव्य आयोजन के दौरान, जहां 'सहकार से समृद्धि' अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता तथा उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, वहीं शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) डॉ. समित शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. शर्मा ने कहा कि चूंकि सहकारिता हमें मिलकर कार्य करने और सामूहिक प्रयासों से सफलता अर्जित करने की प्रेरणा देती है, इसीलिए विभाग का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की इस साझा यात्रा में समाज का कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस अभियान के तहत 114 से अधिक नवाचारों के माध्यम से प्रदेश में विकास की नई संभावनाओं को लगातार साकार किया जा रहा है। समारोह के दौरान एक शानदार सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें डॉ. समित शर्मा सहित सहकारी अधिकारियों—मुरार सिंह जड़ावत, कार्तिकेय मिश्र और राकेश शर्मा आदि ने अपनी बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर टीम भावना, सामूहिक सहयोग एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का एक अनूठा संदेश दिया।

सहकारी बैंकों के अधिकारियों की थपथपाई पीठ, मिला सम्मान

इस गरिमामयी मंच पर बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक पी.के. नाग, सहायक महाप्रबंधक वी.के. मिश्रा, उप महाप्रबंधक सुमन मीणा, बांसवाड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक परेश पंड्या व मुख्य प्रबंधक आशीष गुप्ता, अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक हरीश सिवासिया एवं वरिष्ठ प्रबंधक मुकेश शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार बैंकिंग पी.सी. जाटव, जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार शर्मा, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के उप महाप्रबंधक भंवर लाल बोसाना, सीकर पीएलडीबी सचिव महेन्द्र पाल, जालौर पीएलडीबी सचिव सुनील वीरभान, रामअवतार शर्मा और शांति लाल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

उत्कृष्ट सेवा देने वाले भी हुए गौरवान्वित

साथ ही, समर्थन मूल्य पर खरीद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विष्णुदत्त शर्मा, शंकर लाल धाकड़, राजन कुमार भारती एवं अनिरुद्ध देथा को भी प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए। उपभोक्ता क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कॉनफेड के प्रबंध निदेशक राजेन्द्र सिंह एवं उदयपुर थोक भंडार के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार के साथ-साथ खण्ड एवं इकाई स्तर पर बलविन्दर सिंह गिल, शिरीष वी. चांदे, शिवचरण विजय और सुरेन्द्र सिंह खंगारोत को सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में, प्रधान कार्यालय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले आर.एस. जोधा, अजय उपाध्याय, कल्पना जोशी, वर्षा मीणा, मधु मीणा, किरण सोनी, बृजेन्द्र प्रसाद, गिरवर सिंह, रामरतन चौधरी एवं रामपाल को भी उनकी बेहतरीन कार्यप्रणाली के लिए सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

दी जालोर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
द्वारा आयोजित सहकार सप्ताह (वर्ष 2026-27) के अवसर पर,
ठा. प्रदीपसिंह चौहान (अध्यक्ष, पैक्स-सियाना)
को सहकारिता के क्षेत्र में उनके अत्यंत उल्लेखनीय एवं सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किए जाने पर
हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं
:::: शुभेच्छु ::::
समस्त स्टाफ एवं संचालक बोर्ड सदस्य गण,
सियाना ग्राम सेवा सहकारी समिति
सियाना एवं मिनी सहकारी बैंक सियाना
तहसील-जालोर, जिला-जालोर

मारवाड़ का मित्र
जुड़े और पढ़ें हर पल की खबर
मारवाड़ का मित्र
facebook.com/marwarkamitra
visit,Like and share

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।